(c) In the 1995-96 budget, a subsidy of Rs. 1650 crores has been proposed for imports of fertilizers. During 1994-95, the subsidy borne by the Government on import of fertilizers on Government account was Rs. 1166.02 crores.

(d) and (e) The Maximum Retail Price (MRP) of urea, which is the only fertilizer under statutory price control, has been fixed at Rs. 3320 per tonne excluding local taxes. The MRP of urea, which is uniform throughout the country, was last revised on 10.6.94 from Rs. 2760 per tonne. The State Governments are required to ensure tha urea is sold at the MRP fixed by the Government. The prices of other fertilizers, which are decontrolled, are determined by market forces and may vary from State to State. In order to cushion the impact of increase in prices following decontrol and to establish an equilibrium between imported and indigenous decontrolled fertilizers, the Government has provided a special subsidy scheme on sale of these fertilizers.

Complaints regarding inclusion/exclusion of drug under DPCO

4922. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received representation|complaints about wrong inclusion or exclusion of drugs, under DPCO; and

(b) if so, the details thereof and steps taken to re-include or re-exclude these drugs under current price control order?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) The Government have received representations about inclusion|exclusion of 16 bulk drugs under Drugs (Price Control) Order, 1995. These will be dealt with under the relevant provisions of the "Modifications in Drug Policy, 1986".

Expansion of IFFCO

4923. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has approved the proposal to expand the capacity of the Indian Farmers Fertilizers Cooperative ammonia-urea plant at Phulpur; and

(b) if so, the estimated cost of the expansion plan and the foreign exchange component?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Yes Sir.

(b) The estimated cost of this expansion project is Rs. 993.60 crores including a foreign exchange component of Rs. 342.54 crores.

उर्वरक संयंत्रों के बन्द होने संबंधी समाचार

4924. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल, 1995 के "दि बिजनैस स्टैण्डर्ड" नामक दैनिक समाचार में "फर्टिलाइजर प्लाण्टस इन नार्थ फेस क्लोजर ओवर कोल स्केर्यासिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सच है कि कोयले की अपर्याप्त पूर्ति के कारण रसायनिक खाद का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की उत्पादन की दर गत माहों से कम होती जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उर्वरक संयंत्र कोयले की कम आपूर्ति के कारण अपनी स्थापित क्षमता का अल्प उपयोग कर रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उर्वरक क्षेत्र को इस आकस्मिक संकट से उबारने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) गत कुछ महीनों के दौरान उत्तर में विभिन्न उर्वरक एककों में कोयले के रेक की उपलब्धता बहुत कठिनाई से हो रही है, इस प्रकार किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए कोयले के पर्याप्त भण्डारों के बिना इन एककों को अपना प्रचालन जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है । अब तक रेल संचलन के कारण कोयले की कम उपलब्धता के कारण विभिन्न एककों में समग्र उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, केवल एन एफ एल के भटिण्डा एकक को छोड़ कर जहां कोयले के प्रतिबन्ध के कारण 7 से 13 अप्रैल, 1995 तक 6 दिनों के लिए "शार्ट डाउन" हुआ । स्थिति का सामना करने के लिए एकक ने अस्थायी आधार पर वैकल्पिक ईंधन के उपयोग का सहारा लिया था । इस संयंत्र में उत्पादन दोबारा शुरु हो गया है । कोयले के संचलन के संबंध में स्थिति में सुधार लाने के लिए उर्वरक विभाग ने रेलवे से सम्पर्क बनाया हुआ है ।

रासायनिक खादों में निवेश में कमी संबंधी समाचार-पत्र की रिपोर्ट

4925. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 1995 के "टैलीग्राफ" में "इन्वेस्टमेंट फॉल वरीज प्लान पैनल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रासायनिक-खाद के उत्पादन के क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए एक निर्धारित राशि लक्ष्य के रूप में रखी गई थी ;

(ग) यदि हां तो इस राशि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में रासायनिक-खाद के उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि का पूंजी निवेश किया गया है ; और

(च) क्या सरकार ने वर्तमान समय में कम पूंजी निवेश के कारण स्वदेशी रासायनिक खादों के उत्पादन में कमी होने की स्थिति का आकलन किया है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय 5484 करोड़ रु० है ।